

उन्होंने बहुत से रेस्ट्रिक्शन्स हटा दिये हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या अब सिविल अधिकारियों से मृत सैनिकों के बारे में कोई रिपोर्ट नहीं तलब की जायेगी। अगर नहीं की जायेगी तो उनकी पेंशनों के वास्ते क्या प्रोसीजर होगा।

**Shri Y. B. Chavan:** As I have mentioned in one of the replies, the difficulties of the procedures for finding out the facts about heirs and proving them have now been solved by simplification of the procedures. Even the certificate of the *Sarpanch* of the village or the people who are nearby will be acceptable as final proof. I think this would possibly expedite decisions in these matters.

#### Diwakar Committee Report

- +
- \*620. { **Shri Surendra Pal Singh:**  
**Shri Yashpal Singh:**  
**Shri R. S. Pandey:**  
**Shri Uikey:**  
**Shri Sidheshwar Prasad:**  
**Shri Ramachandra Ulaka:**  
**Shri Dhuleshwar Meena:**  
**Shri Radhelal Vyas:**  
**Shri P. R. Chakraverti:**  
**Shri K. N. Tiwari:**  
**Shri U. M. Trivedi:**

Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 272 on the 30th November, 1964 regarding Diwakar Committee Report on the conditions of small newspapers and state:

(a) whether the said Report has since been submitted to Government; and

(b) if so, its broad recommendations and Government's reaction thereto?

**The Deputy Minister in the Ministry of Information and Broadcasting (Shri C. R. Pattabhi Raman):** (a) No Sir.

(b) Does not arise.

**श्री यशपाल सिंह :** इतने दिनों से सरकार ने यह काम सोंपा हुआ है। हम किस तारीख तक उम्मीद करें कि यह काम हो जायगा ? कोई डेफिनिट डेट दे सकेंगे ?

**Shri C. R. Pattabhi Raman:** There was a period of six months; they could not finish their work. So, the time has been extended. The work is so immense.

**Mr. Speaker:** Whether a date can be given now—that is what they want.

**Shri C. R. Pattabhi Raman:** We are expecting it soon.

**श्री यशपाल सिंह :** जब तक कि ये सिफारिशें न आवें तब तक हिन्दी पत्रों के लिए और अन्य भारतीय भाषाओं के प्रखबारों के लिए सरकार ने क्या निर्णय किया है ? उनके सामने जो दिक्कतें रोज आती हैं, कहीं कोटे की दिक्कत, कहीं विज्ञापन की दिक्कत ? इन को दूर करने के लिए सरकार ने क्या किया है ?

**Shri C. R. Pattabhi Raman:** The extension is up to 11th August, 1965. Even then, they feel that they want more time. Apart from that . . .

**Mr. Speaker:** Has any interim decision been taken or not?

**Shri C. R. Pattabhi Raman:** No, Sir.

**श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :** मैं जानना चाहता हूँ कि किन बजहों से उप समिति ने और अधिक समय की मांग की है, क्या इस के काम के रास्ते में कोई कठिनाई आ गयी है, या सरकार ने इसके टर्म्स ग्राफ रेफरेंस का दायरा बढ़ा दिया है ?

**श्रीमती इंदिरा गांधी :** वह ऐसे पत्रकारों से मिलने के लिए सारे देश में घूम रहे हैं, इसलिए ज्यादा देर लगी है।

**Shri P. R. Chakraverti:** May I know whether the Government has received a representation from this Committee, complaining against the latest decision of the Government to reduce the limit on the permissible extent of advertisement?

**Shri C. R. Pattabhi Raman:** It might have been two or three days ago. But we are not aware of this.

**श्री क० ना० तिवारी :** भ्रमी मंत्री जी ने कहा "बैरी सून"। उन्होंने कहा कि वे जल्दी ही रिपोर्ट आने की आशा कर रहे हैं। यह "बैरी सून" तो आफिशियल जवाब हो गया। पर मैं जानना चाहता हूँ कि इसमें कितना समय लगेगा, दो महीना, चार महीना, 6 महीना, इस में क्या टाइम लिमिट है।

**श्रीमती इंदिरा गांधी :** बाद में उन्होंने ने बताया था कि 11 अगस्त तक एक्सटेंशन मिला है।

भारतीय भाषाओं के समाचारपत्रों के लिये विज्ञापन

+  
\* 216. { श्री प्रकाशबीर शास्त्री :  
श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय भाषाओं के समाचारपत्रों को विज्ञापन देने के सम्बन्ध में जारी की गई हिदायतों की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ;

(ख) क्या सरकार को इस सम्बन्ध में कोई ज्ञापन प्राप्त हुए हैं ; और

(ग) यदि हां, तो उन के सम्बन्ध में सरकार का क्या विचार है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) भारतीय भाषाओं के समाचार-पत्रों को विज्ञापन देने के सम्बन्ध में कोई खास हिदायतें नहीं दी गई हैं।

(ख) जी, हां।

(ग) सरकार का उद्देश्य है कि भारतीय भाषाओं के पत्रों को उत्तरोत्तर अधिक विज्ञापन दिये जायें।

**श्री प्रकाशबीर शास्त्री :** श्रीमन्, क्या मैं यह जान सकता हूँ कि सरकार को जो ज्ञापन प्राप्त हुए हैं भारत य भाषाओं के समाचार-पत्रों की ओर से, उनमें सरकार पर कुछ ऐसे भी आरोप लगाए गए हैं कि सरकारी विज्ञापन उन्हीं समाचार-पत्रों को विशेष रूप से दिए जाते हैं जो सरकार की नीतियों का समर्थन करते हैं, जो जनता का समर्थन करते हैं उनको विज्ञापन नहीं दिए जाते ?

**श्रीमती इंदिरा गांधी :** जी नहीं।

**श्री प्रकाशबीर शास्त्री :** भ्रमी दो तीन दिन पूर्व वित्त मन्त्रालय ने विज्ञापनों के सम्बन्ध में जो नीति निर्धारित की है जिससे समाचार-पत्रों के सामने बड़ी विषम स्थिति उत्पन्न हो गयी है, उस सम्बन्ध में क्या सूचना मंत्रालय से उन्होंने कुछ परामर्श किया था ?

**श्रीमती इंदिरा गांधी :** जी नहीं।

**Shri Jaipal Singh:** May I know whether these advertisements are given on the basis of the circulation of the paper or whether some other criterion is adopted?

**The Deputy Minister in the Ministry of Information and Broadcasting (Shri C. R. Pattabhi Raman):** Circulation is also kept in mind. But I may inform the House that in the current year, April, 1964 to February, 1965, 882 Indian language papers have been used for display advertisements as against 291 in 1954-55. The proportion has increased. We are taking many other things also into consideration.

**Mr. Speaker:** Shri Vidya Charan Shukla.